बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 10

## प्रत्याघात के बाद

**भारतीय** वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर जो हमला किया, उसमें पाकिस्तान के लिए चौंकने जैसा कुछ भी नहीं। इसलिए क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने यह वादा किया था कि इस महीने के आरंभ में कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में शहीद हुए 40 जवानों की मौत का बदला लिया जाएगा। हां, पाकिस्तान को यह आश्चर्य अवश्य हुआ होगा कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों के पायलट कितने सुनियोजित और पेशेवर ढंग से भारी सुरक्षा वाले पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को प्रभावी तरीके से न केवल भेदने में सक्षम रहे बल्कि अपने अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सुरक्षित लौट भी आए। सरकार ने इस हमले की घोषणा करते हुए जिस सतर्कता का परिचय दिया उसने इस वायुसेना के पेशेवराना रुख में चार चांद लगा दिए। विजय का जयघोष और पीठ थपथपाने के बजाय विदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि निशाने पर पाकिस्तानी सेना या आम नागरिक नहीं बल्कि आतंकी थे। बेहद सावधानीपूर्वक 'असैन्य' अभियान शब्द का चयन किया गया जिसमें यह बात निहित थी कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। ऐसे में अगर पाकिस्तान बदले में सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो उसे उकसावे का दोषी माना जाएगा। पाकिस्तान सेना को भी आत्मावलोकन करना होगा क्योंकि वह एक बार फिर सुस्त साबित हुई। इससे पहले 2011 में जब अमेरिकी कमांडरों ने पाकिस्तान के ऐबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। वह इस बात की अनदेखी नहीं कर सकती कि निशाना बनाया गया ठिकाना पाकिस्तान में स्थित था, न कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में।

सरकार की इस बात के लिए भी सराहना की जानी चाहिए कि उसने पुलवामा हमले के बाद विपक्ष को भरोसे में लिया और बिना राजनीतिक निहितार्थों की चिंता किए यह कार्रवाई संभव हो सकी। विपक्ष भी सरकार के समर्थन में खड़ा नजर आया। यह एक दुर्लभ लेकिन स्वागतयोग्य आम सहमति है। सरकार को इस बात का भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लिए जाने और इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान के इनकार करने के बाद उसने विदेशी दूतों को भारत की चिंताओं से समुचित तरीके से अवगत कराया। इस कूटनीति का नतीजा हमारे सामने है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस हवाई कार्रवाई को व्यापक तौर पर स्वीकृति प्रदान की है। यहां तक कि चीन ने भी संयम और रिश्तों में सुधार की वकालत की है। गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है और सेना यह तय करेगी कि वह हवाई हमलों, जमीनी हमलों के माध्यम से उकसावा देने का प्रयास करेगी या आतंकियों की मदद से छद्म लड़ाई को तरजीह देगी। रस्मी बयान आए हैं लेकिन पाकिस्तान यह समझ रहा होगा कि भारतीय सेना बदले में की गई किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होगी और जरूरत पड़ी तो आगे और कार्रवाई की जाएगी। तीनों सेनाओं को पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल को कश्मीर भेजा जा चुका है। सरकार का कहना है कि वे चुनावी ड्यूटी पर हैं लेकिन कहना न होगा कि किसी भी आतंकी गतिविधि के खिलाफ वे बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे। इन हालिया घटनाओं से इतर कश्मीर और आतंकवाद को लेकर मूल चिंताएं बरकरार हैं। भारत के समक्ष कश्मीरियों के गुस्से और नाराजगी का हल तलाश करने की चुनौती बरकरार है ताकि असंतुष्ट युवा जैश जैसे समूहों के आसान शिकार न बनें। अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई से अलगाव की विचारधारा पर नियंत्रण नहीं कायम होगा। संवाद और सहभागिता से यह काम बेहतर तरीके से हो सकता है। यह दोनों देशों के हित में होगा कि तनाव न बढ़े। नियंत्रण रेखा पर अगर एक दूसरे पर हमले किए गए तो दोनों पक्षों में जानें जाएंगी और कुछ नहीं होगा।

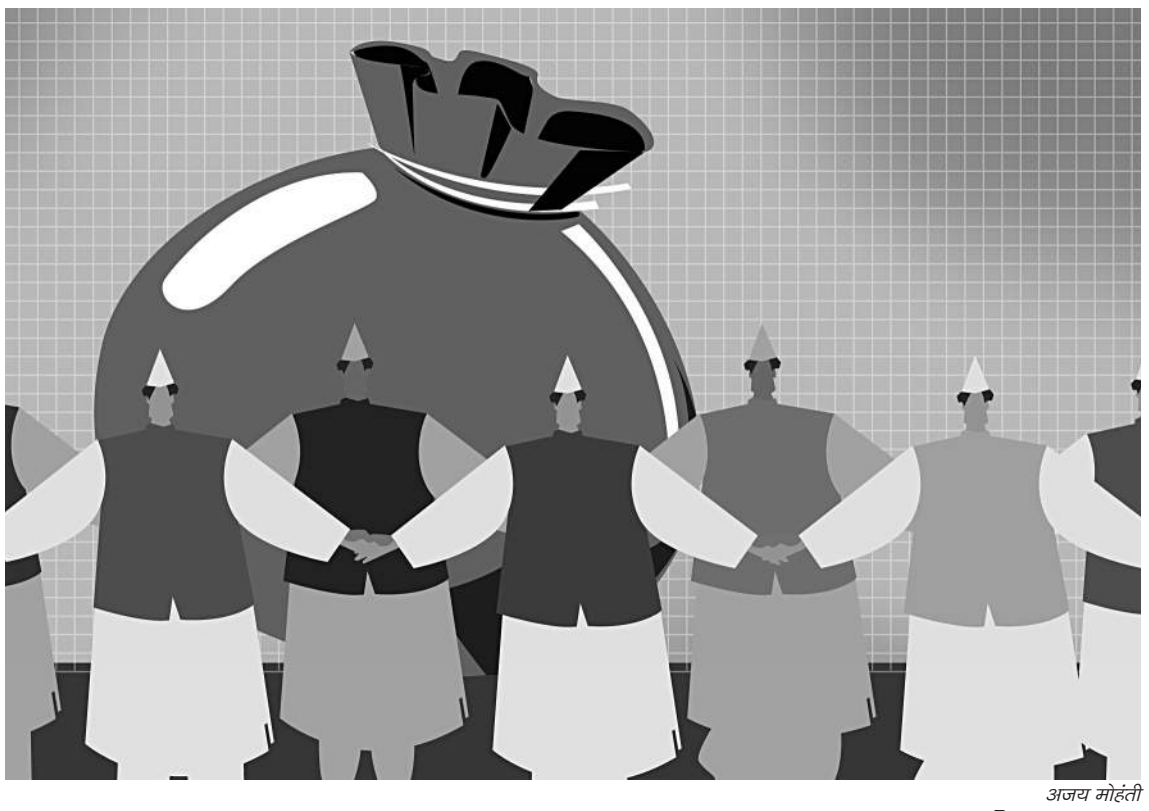

अजय मोहंती

# गठबंधन सरकार और देश की अर्थव्यवस्था

**केंद्र में मजबूत सरकार हो या कथित कमजोर गठबंधन सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं नितिन देसाई**

गठबंधन सरकारें क्या अर्थव्यवस्था के लिए बुरी होती हैं? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि आगामी आम चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद बनने की संभावना बलवती हो रही है। चिंता मौजूदा सत्ताधारी गठजोड़ जैसे सांकेतिक गठबंधन की नहीं बल्कि एक कमजोर गठबंधन से है जहां सत्ता और अधिकार कई साझेदारों के बीच बंटे हुए हों।

अतीत में हमारा पाला कई कमजोर गठबंधनों से पड़ चुका है। ऐसा पहला गठबंधन आपातकाल के बाद सन 1977 में जनता सरकार के रूप में सत्ता में आया और तकरीबन ढाई वर्ष तक चला। दूसरा गठबंधन विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बना और उनकी सरकार दिसंबर 1989 से करीब एक वर्ष तक चली। तीसरा गठबंधन सन 1996 में देवेगौड़ा की सरकार के रूप में सामने आया, उसके बाद सन 1998-99 में वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली गठबंधन सरकार बनी।

गठबंधन के इन तीन दौर में आर्थिक प्रदर्शन के संकेतकों पर गौर करने की आवश्यकता है। सन 1977-79 के पहले दौर पर गौर करें तो आर्थिक मोर्चे पर देश के प्रदर्शन में किसी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिलती है। इस अवधि में वृद्धि दर में इजाफा देखने को मिला और निवेश की दर बढ़ी। इसी प्रकार सार्वजनिक बचत की दर में भी इजाफा हुआ। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की बात करें तो उसकी दर सरकार की कार्यावधि के पहले और बाद में काफी कम रही। चालू खाता भी बेहतर स्थिति में था और अधिशेष की स्थिति दर्शा रहा था।

वर्ष 1990-91 का दूसरा दौर और सन 1996-99 में गठबंधन का तीसरा दौर दर्शाता है कि इस अवधि में वृद्धि और सार्वजनिक बचत में कुछ धीमापन दर्ज किया गया। परंतु वर्ष 1990-91 में चालू खाते का घाटा प्रमुख तौर पर उभरकर आया। यही वह वर्ष था जब विनिमय का भीषण संकट उत्पन्न हुआ। सन 1980 के दशक के आर्थिक इतिहास को अगर तार्किक ढंग से परखा जाए तो इससे यही नतीजा निकलता दिखता है कि इस संकट का मूल पहले की एक दल वाली मजबूत सरकारों के कार्यकाल में निहित है।

इन अपेक्षाकृत कमजोर सरकारों द्वारा शुरू की गई कई पहल आज तक जारी हैं। मिसाल के तौर पर मधु दंडवते के बजट में शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना या फिर पी चिदंबरम द्वारा सन 1997-98 के आम बजट में पेश किया गया 10-20 या 30 फीसदी का आय कर का दायरा।

इससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था प्राय: इस बात से बेपरवाह ही रहती है कि दिल्ली में मजबूत सरकार है या कमजोर। शायद इसका स्पष्टीकरण इस बात में निहित है कि उदारीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक नियंत्रण की प्रक्रिया में बदलाव उत्पन्न किया है और अब नियंत्रण सरकार के बजाय वाणिज्यिक उपक्रमों के हाथ में है। ये वाणिज्यिक उपक्रम मूल रूप से अर्थव्यवस्था को नियंत्रणमुक्त रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि चीजें अधिक से अधिक मांग एवं आपूर्ति से तय होनी चाहिए।

केंद्र सरकार की हस्तक्षेप करने की क्षमता कई मायनों में कम हुई है। सकल जमा निवेश में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी सन 1980 के दशक के मध्य में जहां 60 फीसदी के उच्चतम स्तर पर थी, वहीं अब वह घटकर 25 फीसदी रह गई है। इसका काफी हिस्सा सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित है जिसे न के बराबर या बहुत कम बजट समर्थन मिलता है और ये काफी हद तक बाजार आधारित निजी उपक्रमों के तर्ज पर काम करते हैं। केंद्रीय बजट में वित्तीय हस्तांतरण को छोड़ दिया जाए तो प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय जीडीपी के करीब एक फीसदी के बराबर है और इसका बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में जाता है। राज्य कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका बजट में उल्लिखित विकासात्मक पूंजीगत व्यय जीडीपी के 3 फीसदी के बराबर है। केंद्र सरकार के खुद के बैंक और बीमा कंपनियां हैं लेकिन उसने जिस प्रकार उनका प्रबंधन किया है, उससे मजबूत आर्थिक प्रबंधन की झलक तो कतई नहीं मिलती। जीएसटी के लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का नियंत्रण अब जीएसटी परिषद के पास है। प्रत्यक्ष कर का ढांचा अब सुव्यवस्थित है और केवल सालाना बजट में केवल मामूली बदलाव ही देखने को मिल रहे हैं। मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी अब आरबीआई को सौंप दी गई है। सीमा शुल्क और व्यापारिक नीतियां अब अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अधीन हैं। इसके अलावा उदारीकरण का प्रतिस्पर्धी तर्क भी इस पर लागू होता है। इन तमाम वजहों से केंद्र सरकार का अल्पावधि या मध्यम अवधि के दायरे में अर्थव्यवस्था में किसी भी किस्म का बदलाव लाना केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रह गया है। सरकार नोटबंदी जैसे गैरबुद्धिमतापूर्ण तौर तरीके अपनाकर जरूर हस्तक्षेप करती है जो सही साबित नहीं होते।

ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दिल्ली में गठबंधन सरकार की संभावनाओं को लेकर चिंतित है तो उनसे कहा जा सकता है:

अगर आपके समाचार पत्र या टेलीविजन में कई बार आपको ऐसी दिल्ली के गलियारों में भ्रम फैला होने से जुड़ी खबर दिखाई देती है तो आप सहज रहिए, भले ही केंद्र के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था को अब केंद्र सरकार के कदमों से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है।

अल्पावधि के आर्थिक प्रदर्शन के हमारी राजनीति से अलग होने का यह अर्थ नहीं है कि सरकार लंबी अवधि के विकास के कार्यों की दृष्टि से भी मायने नहीं रखती है।

कृषि से लेकर बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां निजी क्षेत्र को प्रभावी परिचालन की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी खंड-खंड बाजार उपयुक्त नहीं साबित होगा। यहां असली समस्या यह है कि कमजोर और मजबूत दोनों सरकारों से चूक हुई हैं।

कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नौकरशाही और सरकारी संस्थानों को करना होता है। इसलिए राज्य स्तर पर स्थिर सरकार की आवश्यकता है।

गहन विकेंद्रीकरण और वित्तीय अंतरण लंबी अवधि के विकास के लिए जरूरी है। देश के कई राज्य खासे बड़े हैं और राज्यों और नगर निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों में उनके और अधिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

केंद्र सरकार को राजकोषीय संसाधनों को सहयोगित करना बंद करना चाहिए। केंद्र सरकार भी अगर सूक्ष्म विकास प्रबंधन से मुक्त हो तो वह अपना ध्यान रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, वृहद आर्थिक नीति, विदेश व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन, अंतरराज्यीय व्यापार और बुनियादी ढांचा आदि क्षेत्रों पर केंद्रित कर सकती है, जो वास्तव में उसका ही कार्य क्षेत्र है। यही हमारे संविधान की मूल भावना है।

# 'सभी तरह के कैंसर की दवा' महज आशावाद या नई ईजाद

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

**इजरायल** की एक शोध फर्म ने ऐसी जादुई दवा ईजाद करने का दावा किया है जो सभी तरह के कैंसर का इलाज कर सकती है। इसके वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में कैंसर इलाज की इस नई पद्धति का मानव पर परीक्षण भी शुरू कर दिया जाएगा।

यह कई मायनों में असाधारण घटना है। कैंसर की 200 से भी अधिक तरह की किस्में हैं और हरेक तरह के कैंसर की पहचान एवं इलाज की कई पद्धतियां हैं। कैंसर की व्याधि को पूरी तरह दूर कर पाने की दर भी अलग-अलग होती है। खास बात यह है कि किसी भी इलाज को शुरुआती प्रयोगशाला परीक्षणों से लेकर मरीजों पर उसका इस्तेमाल शुरू होने में 10-15 साल का लंबा वक्त लग जाता है। जानवरों पर क्लिनिकल परीक्षण के बाद इंसानों पर परीक्षण होता है और फिर तमाम नियामकीय एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद ही इलाज में उसका इस्तेमाल शुरू हो पाता है। इजरायल के नेस जियोना स्थित निजी शोध फर्म एक्सीलरेटेड इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऐईबीआई) कैंसर इलाज में यह बड़ा दावा करने के बाद से ही चर्चा के केंद्र में है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उसके इस ऐलान पर कई तरह के संदेह जताए हैं।

ऐसे दावों के समर्थन में हमेशा क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़े और विशेषज्ञ समीक्षा-पत्र रखे जाने चाहिए। लेकिन एईबीआई के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। उसका कहना है कि उसने चूहों पर इस पद्धति का क्लिनिकल परीक्षण किया है लेकिन उसके बारे में कोई शोध-पत्र नहीं प्रकाशित किया है।

कैंसर इलाज में नए दौर की शुरुआत के तौर पर पेश किए जा रहे इस दावे में प्रतीकों और अतिशयोक्ति दोनों का समावेश है। एईबीआई ने इस इलाज को 'मुटाटो' यानी मल्टी-टार्गेट टॉक्सिन का नाम दिया है। शोध फर्म के मुख्य कार्याधिकारी डॉ इलेन मोराद ने एक साक्षात्कार में कहा है, 'हम कैंसर कोशिकाओं पर एक साथ हमला बोलने की स्थिति पैदा करते हैं। जिस तरह ऑक्टोपस की कई भुजाएं काम करती हैं। इस मामले में ऑक्टोपस का काम मुटाटो अणु करते हैं और हरेक अणु के आखिर में पेप्टाइड होते हैं जो कैंसर प्रोटीन के साथ क्रिया करके उन्हें रोक देते हैं।' इस अंत:क्रिया से 'ऑक्टोपस' से जुड़े 'टॉक्सिक पेप्टाइड' कैंसर कोशिकाओं में दाखिल हो जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं।

इसमें एक विचार निहित हो सकता है जो कैंसर से जंग में उपयोगी हो सकता है। एक एमिनो एसिड एक साधारण कार्बनिक अवयव होता है जिसमें अन्य तत्त्वों के साथ एक एमीन और एक कार्बाक्सिल समूह भी होता है। एमिनो एसिड जीवन के लिए अपरिहार्य माने जाते हैं क्योंकि वे अकार्बनिक तरीके से बने होते हैं और उन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनते हैं। पेप्टाइड ऐसा अणु होता है जिसमें एमिनो एसिड की दो या उससे अधिक लड़ियां होती हैं।

कैंसर कोशिकाएं प्रोटीन के लक्षणों को दर्शाती हैं। प्रोटीन बड़े एवं जटिल पेप्टाइड की तरह होते हैं जिनमें एमिनो एसिड की कई शृंखलाएं होती हैं। पेप्टाइड अगर कैंसर कोशिकाओं में मौजूद खास प्रोटीन की पहचान कर उन्हें निशाना बना सकें तो वे कैंसर के लिए मारक हो सकते हैं। लेकिन कैंसर कोशिका अगर एक खास पेप्टाइड के निशाने पर है तो वह भविष्य में हमले से बचने के लिए खुद 'लक्षित प्रोटीन' पैदा कर सकती है।

जेम्स पी एलिसन और तासुकू होंजो को नकारात्मक प्रतिरक्षा नियमन का निषेध कर कैंसर निदान में की गई खोज के लिए शरीर-क्रिया विज्ञान में 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन विशेषज्ञों ने कैंसर कोशिकाओं में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर होने वाले हमलों को नाकाम कर देते हैं। पेप्टाइड शरीर की प्रतिरक्षा वाले इन चेकप्वाइंट की पहचान करने और उन्हें बाहर करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा होने पर कैंसर कोशिका दवाओं के असर से बच नहीं सकती हैं।

मुटाटो तकनीक में विभिन्न कैंसर-लक्षित पेप्टाइड के साथ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाले ताकतवर टॉक्सिन को समाहित करने पर जोर है। सशक्त टॉक्सिन के साथ कम-से-कम तीन हमलावर पेप्टाइड का इस्तेमाल कर एईबीआई यह सुनिश्चित करना चाह रहा है कि इस इलाज के बाद भविष्य में कैंसर दोबारा नहीं सिर उठा पाएगा। कुछ कैंसर ट्यूमर जैविक कवच भी पैदा करते हैं जो एंटीबॉडी जैसे बड़े अणुओं को पहुंचने से रोकने का काम करता है। मुटाटो दृष्टिकोण में ऐसे जैविक कवचों के भीतर सेंध लगाने की क्षमता रखने वाले बहुआयामी शिकंजा कसने पर जोर दिया गया है। मोराद का कहना है कि मुटाटो पेप्टाइड बहुत छोटे आकार (12 एमिनो एसिड लंबे) के हैं और उनकी कोई तय संरचना भी नहीं होने से वे आसानी से कवच से पार निकल सकते हैं। एईबीआई के मुताबिक, उसने चूहे पर पहला प्रायोगिक परीक्षण पूरा कर लिया है जिसमें कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने के साथ ही चूहे की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई असर भी नहीं देखने को मिला है। अब परीक्षण का दायरा चूहों से इतर जानवरों तक विस्तारित हो जाएगा। इंसानों पर परीक्षण शुरू करने के पहले इसे फॉर्मूलाबद्ध किया जाएगा और उसके कायदे-कानून तय होंगे।

लेकिन एईबीआई के दावों को लेकर कई बिंदुओं पर सवाल खड़े होते हैं। बिना किसी साक्ष्य के उसके दावे पर कितना भरोसा करें? वह जिस बहुआयामी नजरिये की बात कर रही है, वह कीमोथेरेपी में मानक प्रक्रिया है और उससे कैंसर पर हमेशा के लिए रोक लगा पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। इस बात की संभावना कम ही है कि सभी तरह के कैंसर के इलाज में यह पद्धति कारगर हो पाएगी।

तो क्या इजरायली फर्म का दावा महज आशावाद है? या फिर यह सही मायने में नई खोज है? या फिर इस खबर के जरिये एक अनजान-सी कंपनी पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है? बहरहाल इजरायल में उच्च तकनीक एवं जीवन विज्ञान उद्योग के प्रतिनिधि संगठन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ने एईबीआई के दावों को 'गैर-जिम्मेदार और इजरायली उद्योग की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक' बताते हुए उनकी आलोचना की है।

## कानाफूसी

### जैसे को तैसा

मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी एक बार फिर खबरों में हैं और इस बार भी वजह नकारात्मक ही है। पिछले दिनों शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात के दौरान एक असंतुष्ट कार्यकर्ता ने जब उनसे कम मानदेय की शिकायत की तो मंत्री ने पलटकर कहा कि मानदेय शिक्षा दीक्षा की काबिलियत के आधार पर ही दिया जाता है। कार्यकर्ता ने पलटकर मंत्री महोदया से उनकी ही शिक्षा पूछ ली। सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मंत्री महोदया केवल कक्षा 12वीं पास हैं। जाहिर है वह चुपचाप आगे बढ़ गईं। करीब एक महीने पहले भी मंत्री चर्चा में थीं जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर लिखित भाषण पढ़ने में बार-बार अटकने के बाद उन्होंने भाषण जिलाधिकारी की ओर बढ़ाते हुए कहा था- आगे कलेक्टर साहब पढ़ेंगे।

### महिला टैक्सी सेवा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में महिला सशक्तीकरण की अपनी योजना के तहत पिंक टैक्सी सेवा की शुरुआत की। महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली गुलाबी और सफेद रंग की ये टैक्सियां राज्य सरकार की गतिधारा योजना का लाभ उठा सकेंगी। अन्य कारों के लिए जहां एक लाख रुपये प्रति कार की दर से सब्सिडी दी जाती है, वहीं पिंक टैक्सी की मालिक महिलाओं को डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब तक 36 हजार से अधिक लोग गतिधारा योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत चूंकि अब महिलाओं को अधिक लाभ हो रहा है लेकिन यात्रियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये महिला टैक्सीचालक महिला पुरुष दोनों तरह के यात्रियों की सेवा करेंगी।

## आपका पक्ष

### सामाजिक मुद्दे पर ऑस्कर पुरस्कार

माहवारी के समय महिलाओं को होने वाली दिक्कतों पर बनी लघु फिल्म पीरियड-एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। फिल्म में माहवारी के समय होने वाली समस्या और नैपकिन की अनुपलब्धता को दर्शाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन रायका जेहताबची ने किया है। इससे पहले भी माहवारी पर अक्षय कुमार की पैडमैन फिल्म आ चुकी है। इस फिल्म में भी माहवारी के दौरान नैपकिन कितना जरूरी है यह दर्शाया गया है। तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें जागरूक करने के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म अक्सर समाज को एक संदेश देती है। फिल्म लोगों को जागरूक करने का एक बेहतर साधन भी है। फिल्मों से ही सीख लेकर लोग अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। सामाजिक मुद्दे पर पहले भी कई फिल्में

ऑस्कर पुरस्कार ग्रहण करने के बाद फिल्म निर्देशिका रायका जेहताबची (दाएं) -पीटीआई

बन चुकी हैं। फिल्म पिंक में महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा महिला सशक्तीकरण को दर्शाया गया है। इस फिल्म में महिलाओं की आजादी तथा समाज में खासकर युवाओं में महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाया गया है। फिल्म दंगल में हरियाणा की लड़कियों को कुश्ती लड़ना दिखाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि लड़कियां भी लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। फिल्म मॉम में एक मां की बदला लेने की कहानी दर्शाया गया है। इस तरह की सामाजिक फिल्म समाज में चेतना लाती है। फिल्मों से प्रेरित होकर लोग उसकी अच्छाइयों पर अमल करते हैं। देश में सामाजिक बुराइयां इतनी अधिक हैं कि उन पर फिल्म बनाने से पुरस्कार मिल रहे हैं। देश में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। इसके लिए फिल्म एक बेहतर साधन है।

*प्रियंका कुमारी, नोएडा*

### भूमिहीन किसानों को मिले सहायता

अंतरिम बजट में घोषित आय सहायता योजना, पीएम किसान योजना का फायदा भूस्वामी किसानों को मिलेगा। किसानों को एक साल में तीन किस्त में 6,000 रुपये मिलेंगे। सरकार को भूस्वामी के अलावा भूमिहीन किसानों को भी इस योजना के दायर में लाना चाहिए। वहीं एक साल में 6,000 रुपये काफी कम रकम है। इतनी रकम से ज्यादा किसानों को फसल नुकसान होने पर घाटा होता है। इसके अलावा किराये की जमीन पर खेती करने के कारण उन्हें जमीन का किराया भी देना पड़ता है। इससे बेहतर यह होता कि सरकार उपजाऊ जमीन किसानों को कम कीमत पर प्रदान करे जिससे वह अच्छी तरह खेती कर सके। किराये पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों पर चौतरफा मार पड़ती है। पहला उन्हें खेत का किराया देना पड़ता है। दूसरा फसल नुकसान होने की स्थिति में नुकसान तो होता ही है, इसके अलावा खेत का किराया भी भरना पड़ता है। उपज होने के बाद उसे मंडी ले जाने का खर्च लगता है और मंडी में उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से उन्हें घाटा सहना पड़ता है। अत: सरकार को भूमिहीन किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए।

*राकेश जैन, सतना*

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**